

बस यूं ही...

शांता पारेख, इन्दौर 9425311944

प्रयोगशाला

सबसे फालतू तो शिक्षा विभाग हैं जिसे प्रयोगशाला हर विभाग की कह सकते हैं. फरवरी में परीक्षा हैं अध्यापक एस आई आर में लगे हैं, वहां भी सिर पर तलवार लटक ही है, लोग विवाह समारोह में गए हैं, जब आपों, जानकारी दे देंगे.वह एक कहानी हैं जिसमें तेल का भरा कटोरा लेकर एक बंदा महल देखने जाता हैं, शर्त ये कि तेल गिरा तो गर्दन उड़ा डी जाएगी, उसने महल नहीं देखा सिर्फ कटोरा देखा. कभी जनगणना, परिवार नियोजन, चुनाव ड्यूटी में लगते माटसाब, उनके बच्चे स्कूल की धूल सिर पे डाल खुश होते रहते, हंसो मत उनको क्लास डिजिटल हैं व स्मार्ट टी वी हैं.

बस कभी कभी बिजली आती हैं बाकी दर्शनीय वस्तुओ का दर्शन करो, जब घंटी बजे मध्याह्न भोजन करो भर पेट. घर जाके सरकारी बाटा अनाज खा लेंगे ही. कुपोषित मा हैं बाप हर गली में खुले मदिरालय का स्थायी उपभोक्ता हैं. हम तेजी से बढ़ते देश में रहते हैं जी डी पी शानदार हैं गुरुपूर्णिमा व शिक्षकदिवस पूरी श्रद्धा से मनाते हैं, सभी संस्थाएं आदर से बुला कर शौल श्रीफल देती व मंच पर मन की बात कहने का अवसर देती हैं. शिक्षक तीन दिन राष्ट्रपति के मेहमान बनते व शानदार शिक्षक सम्मान लेके आते हैं. धन्य प्रयोगशाला, व शालाये हैं हमें गर्व हैं कि गुरु को भगवान से बड़ा माना हैं।

बिना वैध अनुमति के नहीं होंगी पेड़ कटाई, हाईकोर्ट ने रोक लगा सरकार से ट्री ऑफिसर नियुक्त करने का कहा



इन्दौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगापीठ में शहर में लगातार पेड़ों को काटे जाने के संदर्भ में मप्र वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 की धारा 4 और 6 के प्रावधानों के पालन को लेकर सवाल उठाते लगाई याचिका पर सुनवाई दौरान सख्त रुख अपनाते कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जब तक राज्य सरकार विधिवत रूप से ट्री ऑफिसर की नियुक्ति नहीं करती, तब तक किसी भी अनुमति के आधार पर पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकती।

याचिका डॉ. अमन शर्मा द्वारा दायर की गई है। सुनवाई दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिनव धनोतकर ने कोर्ट को बताया कि अधिनियम के तहत ट्री ऑफिसर नियुक्त करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। इसके बावजूद इंदौर नगर निगम आयुक्त को अधिसूचना के जरिए ट्री ऑफिसर घोषित किया गया। इसी हेतिसयत से वे नगर निगम की विभिन्न परियोजनाओं के लिए पेड़ कटाई की अनुमति वे स्वयं ही दे रहे हैं।

कोर्ट ने इसे हितों के टकराव का मामला मानते हुए अनुचित ठहराते अपने 18 दिसंबर 2024 के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस एजेंसी द्वारा विकास कार्य किया जा रहा हो, वही एजेंसी स्वयं को पेड़ काटने की अनुमति नहीं दे सकती। इसी आधार पर पहले भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे कि वह राजपत्रित अधिकारी से कम रैंक के नहीं होने वाले वन अधिकारी को ट्री ऑफिसर नियुक्त करे। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि राज्य सरकार ने अबतक ट्री ऑफिसर की नियुक्ति नहीं की है। जिस पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई और राज्य सरकार को निर्देशित कर कहा-पेड़ कटाई के लिए ट्री ऑफिसर की नियुक्ति करें।

सरकारी वादा वया सरकार अमी भी असमंजस में है?

समाचार। सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के नारे से समानता का वादा किया था। टिप्पणी। भला हो सुप्रीम कोर्ट का जो यूजीसी को नई गाइडलाइन पर रोक लगा दी, वरना सरकारी वादा झूठ हो जाता ? बी एल शर्मा अकिंचन तराना-उज्जैन

SMFG India Credit Company Limited advertisement. It includes the company name, address, and a table with columns for 'क्र.', 'प्रयोग/साहस/समाप्त/प्रमाण/वर्ष का नाम एवं खाता क्रमांक', 'दिनांक नोटिस की तिथि एवं राशि', 'संख्या रखाई सम्पत्ति का वर्णन', and 'आविष्यत की तिथि व प्रकार'. It also contains a detailed notice regarding the company's financial health and legal proceedings.

भागीरथपुरा में मौतों को लेकर कांग्रेस का धरना ... जीतू पटवारी के नेतृत्व में राजवाड़ा पर हुआ आंदोलन



इन्दौर (नवीन मोर्य)। भागीरथपुरा में दूषित पानी से 31 लोगों की मौत हो जाने के मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के द्वारा राजबाड़े पर धरना दिया गया।

कांग्रेस के शहर अध्यक्ष चिट्टू चौकसे, जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के प्रभारी दीपू यादव ने बताया कि भागीरथपुरा में हुई इस

राजबाड़ा में जुटे कांग्रेसी, मृतकों के परिवार को एक करोड़ मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग कांग्रेस ने की मृतकों के परिजनों को एक करोड़ के मुआवजे की मांग

घटना के संदर्भ में हर पीड़ित के परिवार



को एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने सरकारी नौकरी देने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की कांग्रेस ने मांग की है।

इसके साथ ही कांग्रेस की मांग है कि नागरिकों को शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए ताकि शहर में कहीं भी और भागीरथपुरा जैसा हादसा नहीं हो। इसके साथ ही इस घटना के लिए जिम्मेदार प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्पमित्र भार्गव

के द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया जाए। इन मांगों को लेकर कांग्रेस के द्वारा राजबाड़ा पर धरना दिया गया। इस धरने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस की इंदौर संभागी प्रभारी सचिव उषा नायडू, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल हुए। कांग्रेस ने कहा है कि इन मांगों को लेकर उसके द्वारा पूर्व से ही अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आगे भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए निरंतर रहेगा। ध्यान रहे कि इसके पहले कांग्रेस न्याय यात्रा

निकालकर इन पीड़ितों को न्याय देने की आवाज बुलंद कर चुकी है। राज्य सरकार के द्वारा अभी तक मृतकों के परिवार के लिए कोई मुआवजा भी घोषित नहीं किया गया है। इंदौर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के फंड से मात्र 2-2 लाख रुपए की राहत राशि दी गई है। कांग्रेस की मांग है कि मृतकों के परिजन को एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और दोषी अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो...।

इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर पर विकसित होगी टीपीएस योजनाएं

इंदौर। शासन ने तय किया है कि जितने भी महत्वपूर्ण फोरलेन कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं उन पर आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक सहित आईटी से जुड़ी गतिविधियों को लाया जाए, जिसमें इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर भी शामिल है।



50 किलोमीटर लम्बा यह फोरलेन एक्सप्रेस-वे सिंहस्थ के महेनजर निर्मित किया जा रहा है, जिसमें भू-अर्जन की प्रक्रिया भी इन दिनों चल रही है। इस कॉरिडोर सहित अन्य का निर्माण मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम यानी एमपीआरडीसी द्वारा कराया जा रहा है और अब उसमें कंसल्टेंट की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया है, जिसके लिए टेंडर के जरिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इसमें भोपाल के पश्चिमी ग्रीन फील्ड

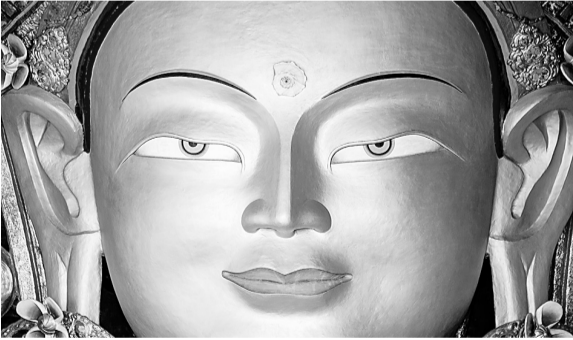
बायपास सहित अन्य प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। शासन का मकसद है कि इन फोरलेन कॉरिडोर के दोनों तरफ विभिन्न तरह की गतिविधियां विकसित कराई जाए, ताकि इन पर यातायात का दबाव तो बना ही रहे, साथ ही शहर विस्तार से जुड़ी योजनाओं का भी लाभ मिल सके। अभी इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के निर्माण की भी प्रक्रिया चल रही है, जिस पर लगभग 2

हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी और इंदौर के पितृ पर्वत के पास से यह कॉरिडोर शुरू होगा, जो उज्जैन के चिंतामण गणेश तक बनेगा। इस फोरलेन एक्सप्रेस कंट्रोल्ड हाइवे के दोनों तरफ सर्विस लेन, 34 अंडरपास, दो फ्लायओवर और एक रेलवे ओवरब्रिज भी निर्मित होना है। कुछ समय पूर्व ही लुधियाना की कम्पनी को इसके निर्माण का ठेका दिया गया है और अभी सांवर के 20

सभी प्रमुख कॉरिडोर पर आएंगी आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक गतिविधियां, एमपीआरडीसी करेगा कंसल्टेंट की नियुक्ति, टेंडर के जरिए बुलवाए प्रस्ताव

और हातोद के 28 गांवों की जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है। इसी तरह पिछले दिनों ही कैबिनेट ने भोपाल पश्चिमी ग्रीन फील्ड बायपास को भी मंजूरी दी और उसके साथ पूर्वी बायपास भी निर्मित होना। इसी तरह उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड राजमार्ग और सिंहस्थ बायपास के अलावा जबलपुर रिंग रोड और उससे जुड़ने वाली सड़कों पर भी इस तरह की गतिविधियां शुरू की जाएगी।

हेमशंकर पाठक के छायाचित्रों की तीन दिवसीय प्रदर्शनी



इंदौर। इन्दौर के वरिष्ठ फोटोग्राफर हेमशंकर पाठक के छायाचित्रों की तीन दिवसीय प्रदर्शनी प्रीतमलाल दुआ सभागृह में 6 से 8 फरवरी तक लगाने जा रही है। इसमें हेमशंकर पाठक के रंगीन और श्वेत-श्याम 81 छायाचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। इनमें एक तरफ फोटोग्राफी की कलात्मकता दिखाई देगी तो दूसरी तरफ जीवन के स्पंदन को महसूस किया जा सकेगा। प्रदर्शनी दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे सभी कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी।



सिस्ट्रो टेलीलिंक लिमिटेड CIN : LI9201MP 1992 PLC 0006925 पंजीकृत कार्यालय : 206, एरियन हाईस्ट्र, एबी रोड इंदौर, इंदौर मध्यप्रदेश, भारत 452010 फोन नं. 0731-2555022, फैक्स नं. 0731-2555722 ई मेल आईडी cistrotelink@gmail.com वेबसाइट www.cistrotelink.com

Advertisement for Cistrotelink Limited. It details the company's registration, address, and contact information. It also includes a notice regarding the appointment of a new director and the company's financial health, mentioning a court order to freeze the accounts of the former director.

मावर्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की आमसभा

इंदौर। मावर्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव का जसविंदर सिंह आज 4 फरवरी शहर में रहेगे। दोपहर 12:30 से इंदौर पार्टी की जिला कमेटी बैठक को संबोधित करेगे। बैठक में भाजपा की विनाशकारी अमेरिका के दबाव में लाई गई नीतियों का विस्तृत खुलासा रखेंगे और उससे कृषि क्षेत्र के अलावा 12 फरवरी चार मजदूर विरोधी श्रम कानून को लेकर श्रम संगठनों के संयुक्त आह्वान पर होने वाली देशव्यापी हड़ताल में पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका को स्पष्ट करेंगे। आर्थिक दरिद्रता की ओर बढ़ाने वाले बजट को लेकर शाम 4:00 बजे रुस्तम के बगीचे पर होने वाली सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी जिला सचिव का अरुण चौहान, पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य कैलाश लिंगोदिया, सीटू जिला सचिव सिरावत, भागीरथ कच्छवाह ने जनसंगठन के साथियों को आम सभा में अपने साथियों के साथ शामिल होने की अपील कि है।

A cartoon illustration titled 'कार्टून कोना...' showing two characters in a conversation. One character says, 'जिस घर में माल ज्यादा हो, चोरी वहां करनी चाहिए' (Where there is more wealth, theft should be done there). The other character replies, 'पर राजनीति में इसका उलट है, कमजोर को अगुवा करना आसान है' (But in politics, it's the opposite, it's easier to lead the weak). The cartoon is signed 'राम विनोद'.

Table titled 'पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल रेलिच कार्य' (Western Railway - Ratlam Division Reliwork Work). It lists various railway projects and their estimated costs in lakhs of rupees. The table includes columns for project name, estimated cost, and actual cost.